NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

# युवा सहकार

www.nycsindia.com
अक्टूबर 2025, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

## भारतीय सहकारिता को मिली नई पहचान

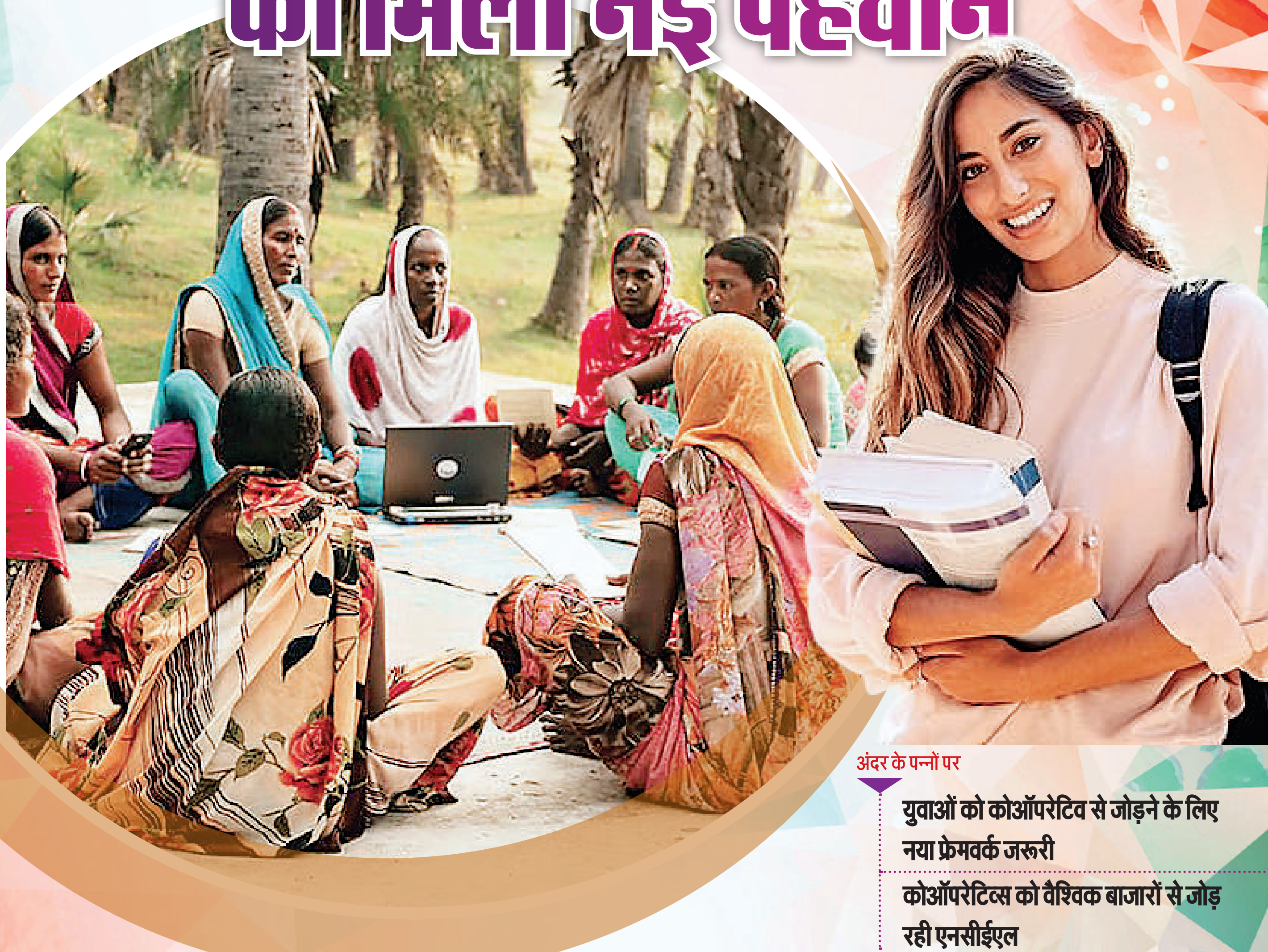

अंदर के पन्नों पर

युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए नया फ्रेमवर्क जरूरी
कोऑपरेटिव्स को वैश्विक बाजारों से जोड़ रही एनसीईएल

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

# SERVING **FARMERS** **TO GROW** BOUNTIFUL

KRIBHCO world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs and other diversified businesses.

## KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

**Registered Office:** A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 | **Phone: 011-29243412**
**Corporate Office:** KRIBCHO BHAWAN, A 8-10, Sector-1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) | **Phones:** 0120-2534631/32/36
**Website:** www.kribhco.net | **KRIBCHO Kisan Helpline:** 0120-2535628 | **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

**OUR PRODUCTS**

Neem Coated Urea | DAP | MOP | NPK | NPS | MAP | Liquid Bio Fertilizers | Certified Seeds | Hybrid Seeds
City Compost | Zinc Sulphate | Natural Potash | Sivarika | Rhizosuper

# युवा सहकार

वर्ष : 02, अंक-04, अक्टूबर-2025



## निदेशक मंडल
### एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता
दर्शन सोलंकी (विशेष आमंत्रित)
देवेन्द्र सिंह (विशेष आमंत्रित)
रामचंद्र दत्तात्रेय कुलकर्णी (सीईओ)



## कार्यालय

**नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)**
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

---------------

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं मित्तल प्रिंट एन पैक, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

---------------

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

---------------

NYCSIndia


## अनुक्रमणिका

सहकारिता की नई गाथा लिख रहा भारत 04

कृभको अध्यक्ष बने वी. सुधाकर चौधरी 05

06 भारतीय सहकारिता को मिली नई पहचान

16 युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए नया फ्रेमवर्क जरूरी

कोऑपरेटिव्स को वैश्विक बाजारों से जोड़ रही एनसीईएल 18

डेयरी सेक्टर में बनेंगे 75 हजार कोऑपरेटिव्स 22

एनवाईसीएस ने जरूरतमंद बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री 24

एनवाईसीएस के रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़ 25

अन्न भंडारण से ग्रामीण युवा होने लगे सशक्त 26

शुभमन गिल को वन डे की भी कप्तानी 28

सोच बदली तो बदल गई जिंदगी 30

# सहकारिता की नई गाथा लिख रहा भारत

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सहकारिता मंत्रालय ने देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरुक किया है। इसका असर यह हुआ है कि अब घर-घर में सहकारिता की चर्चा होने लगी है। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना सहकारी क्षेत्र को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय सहकारी आंदोलन के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। इससे  सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अब समापन की ओर बढ़ रहा है। भारतीय सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने और इसका उज्ज्वल भविष्य तय करने में इस वर्ष का महत्वपूर्ण योगदान स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी आधुनिक भारतीय सहकारिता की बात होगी, इस वर्ष को जरूर याद किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला भारत के प्रयासों से ही किया गया। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की औपचारिक शुरूआत नई दिल्ली में की गई जिसका भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं उनसे भारतीय सहकारिता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है।

इस एक वर्ष में न सिर्फ देश में पहली बार त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, पहली बार नमक उत्पादकों के लिए नमक कोऑपरेटिव बनाई गई, बल्कि नई सहकारिता नीति लागू करने, परिवहन क्षेत्र में सहकारिता के क्रांतिकारी कदम के रूप में सहकार टैक्सी शुरु करने जैसे बड़े कदम उठाए गए। इसके अलावा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी की स्थापना की गई, श्वेत क्रांति 2.0 के तहत दुग्ध उत्पादन में सहकारिता क्षेत्र का योगदान बढ़ाने और डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए तीन नई राष्ट्रीय सहकारी समिति बनाने की घोषणा सहित अन्य दर्जनों पहल की गई। इन पहलों से भारतीय सहकारिता तो मजबूत होगी ही, रोजगार के नए विकल्प के रूप में भी इस क्षेत्र को पहचान मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सहकारिता मंत्रालय ने देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरुक किया है। इसका असर यह हुआ है कि अब घर-घर में सहकारिता की चर्चा होने लगी है। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना सहकारी क्षेत्र को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय सहकारी आंदोलन के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। इससे  सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रमों में सहकारिता को एक विषय के रूप में शामिल करने के फैसले से भी यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक बेहतर रोजगार विकल्प के रूप में उभरेगा। सहकारी क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए सहकारिता मंत्रालय के 100 से अधिक प्रभावी पहलों के माध्यम से सहकारिता ने आज गांवों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और किसानों की समृद्धि के द्वार खोल दिया है। इससे देश की तकरीबन 30 करोड़ से अधिक सदस्यों वाले क्षेत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अपने गठन के बाद से भारतीय सहकारिता को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 121 वर्ष पहले 1904 में संगठित रूप से सहकारिता की शुरूआत के बाद इसे आधुनिक और प्रभावी दिशा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद ही मिली। इसी दौरान देश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की धाक जमाने में सफलता मिली है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें सहकारिता क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण होगा। आने वाला समय भारत का है। सरकार के विभिन्न पहलों से अगले कुछ वर्षों में वैश्विक सहकारिता की कमान भारत के हाथों में होगी। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में शामिल है।■

**प्रकाश चंद्र साहू**
**अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड**

# कृभको अध्यक्ष बने वी. सुधाकर चौधरी

## डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव बने उपाध्यक्ष जो आईसीए-एपी के भी हैं अध्यक्ष

**युवा सहकार टीम**

आंध्र प्रदेश की सहकारिता से जुड़े नेता और व्यवसायी वल्लभनेनी सुधाकर चौधरी को सर्वसम्मति से देश की प्रमुख सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) का अध्यक्ष और डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव को उपाध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले सुधाकर चौधरी इसके उपाध्यक्ष और डॉ. यादव करीब दो दशक से अध्यक्ष थे। सहकारिता क्षेत्र के दिग्गज डॉ. यादव इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस-एशिया पैसिफिक (आईसीए-एपी) के भी अध्यक्ष हैं। इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले भारतीय हैं। देश की नंबर दो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव में दो दशक बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ है।

कृभको के निदेशक मंडल का चुनाव इस साल जनवरी में ही हो गया था, लेकिन सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) ने विभिन्न कारणों से इसके नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किए थे। अगस्त में जब इसकी घोषणा की गई तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का रास्ता साफ हो गया। अध्यक्ष वी. सुधाकर चौधरी और उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव के साथ-साथ निदेशक मंडल में डॉ. बिजेंद्र सिंह, भंवर सिंह शेखावत, मगनलाल धनजीभाई वडाविया, राजन्ना राजेन्द्र, भीखाभाई जवेरभाई पटेल, बिपिनभाई नरनभाई पटेल, कविता मंजीरी परीडा, अजय राय और शिल्पी अरोड़ा शामिल हैं।

अध्यक्ष सुधाकर चौधरी ने सभी निदेशकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'कृभको किसानों के हितों को केंद्र में रखकर सहकारी सशक्तीकरण, उर्वरक उत्पादन में नवाचार और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह नेतृत्व परिवर्तन कृभको की देशभर के लाखों किसानों की सेवा की निरंतर यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ता है।' सहकारी आंदोलन और कृषि क्षेत्र में वी. सुधाकर चौधरी के व्यापक अनुभव से किसानों को सशक्त बनाने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने का कृभको का मिशन और सशक्त होगा। साथ ही, डॉ. चंद्रपाल सिंह के व्यापक अनुभव, विशेषज्ञता और सहकारी मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से संस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी।

वी. सुधाकर चौधरी मोहन स्पिनटेक्स इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। वे आंध्र प्रदेश स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए), भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई), आंध्र प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन और भारतीय सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की प्रबंध समितियों के सदस्य भी हैं। वे आंध्र प्रदेश की कई सहकारी समितियों के बोर्ड में भी हैं।

चंद्रपाल सिंह यादव करीब दो दशक तक इस संस्था के अध्यक्ष रहे। नए नियम के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी संस्था का लगातार दो बार अध्यक्ष रहने के बाद तीसरी बार अध्यक्ष नहीं बन सकता है। इसलिए उन्हें अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष बनाया गया है।

## अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

# भारतीय सहकारिता को मिली नई पहचान

**अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में मंत्रालय की बड़ी पहलों से सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल**

**कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, नई सहकारिता नीति, सहकार टैक्सी जैसी हुई बड़ी घोषणाएं**

**केंद्र सरकार की कारगर पहल से वैश्विक सहकारिता की कमान भारत के हाथों में होगी**

**सहकारी बैंकों को सबलता प्रदान करेगा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया की पहल**

**युवा सहकार टीम**

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की आवाज बुलंद हुई है। दुनिया की करीब एक चौथाई सहकारी संस्थाओं वाली भारतीय सहकारिता की आवाज को गंभीरता से लिया जाने लगा है। तकरीबन 30 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली सहकारिता की जड़ें मजबूत हुई हैं। वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से इस क्षेत्र को नई दिशा मिली है। इस अल्प समय में केंद्र सरकार ने सहकारिता को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसी दौरान देश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता की धाक जमाने में सफलता मिली है। देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सुधारों की लंबी

प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका नतीजा दिखने लगा है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सरकार ने देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरुक किया है। नये मंत्रालय के गठन के बाद के चार वर्षों में सहकारी क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए मंत्रालय की 100 से अधिक प्रभावी पहलों के माध्यम से सहकारिता ने आज गांवों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और किसानों की समृद्धि का द्वार खोल दिया है। व्यापक कानूनी और प्रशासनिक सुधारों सहित सहकारिता की सबसे निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाए जाने से न सिर्फ ग्रामीण आबादी को इसका फायदा मिल रहा है, बल्कि रोजगार और कारोबार के भी नए अवसर खुल रहे हैं।

वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय में भारत की अहम भूमिका रही है। इसके समापन में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजनों में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं उनसे भारतीय सहकारिता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। देश में पहली बार त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का गठन हो, नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का गठन हो, देश में पहली बार नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत हो, दुग्ध क्रांति 2.0 की शुरुआत हो, डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को बढ़ावा देने के लिए तीन नई कोऑपरेटिव बनाने की घोषणा सहित अन्य महत्वपूर्ण कदमों से भारतीय सहकारिता नई उड़ान भर रही है। इसके अलावा इससे वैश्विक सहकारिता आंदोलन को भी नई दिशा मिल रही है। इन पहलों की बदौलत आने वाले वर्षों में वैश्विक सहकारिता की कमान भारत के हाथों में होगी।

**भारत के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। इसके समापन में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयोजनों में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं उनसे भारतीय सहकारिता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है।**

फाइल फोटो

**अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सहकारिता मंत्रालय ने देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया है। नये मंत्रालय के गठन के बाद चार वर्षों में सहकारी क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए मंत्रालय के 100 से अधिक प्रभावी पहलों के माध्यम से सहकारिता ने आज गांवों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और किसानों की समृद्धि का द्वार खोल दिया है।**

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के कोने-कोने में आयोजित सहकारिता सम्मेलनों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान सहकारिता की अलख जगाने वालों की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। उन्होंने सहकारिता के मंत्र की महिमा के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गरीबी, कुपोषण और बेघर लोगों के हितों का ध्यान सहकारिता के माध्यम से रखा जा सकता है। किसानों को उनकी खेती की जरूरत के सभी इनपुट और उपज की खरीद में सहकारिता की भूमिका का महत्व समझाया।

भारत में सहकारिता प्राचीन समय से ही जन-जीवन का आधार रहा है। हमारे कृषि प्रधान समाज में तो यह रोजमर्रा के कामकाज का एक अभिन्न हिस्सा है। 121 वर्ष पहले 1904 में संगठित रूप से सहकारिता की शुरुआत के बाद इसे आधुनिक और प्रभावी दिशा वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मिली। आज भारत में सहकारिता की जड़ें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में मजबूत है। उसी गुजरात से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह आते हैं। इसलिए उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सहकारिता में कितनी क्षमता है। इसे देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना की है और इसी राह पर आगे चलते हुए सहकारिता को विकसित भारत का आधार बनाने का लक्ष्य रखा है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर जो तीन सबसे बड़ी पहल की है, उनमें त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लागू करना और सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा शामिल है। इनके अलावा अन्य दर्जनों पहल की गई है जिससे भारतीय सहकारिता को नई दिशा और पहचान मिली है। इनसे सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल बनाने में भी मदद मिलेगी।

## त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी

अंतरराष्ट्रीय वर्ष के दौरान ही सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध को बढ़ावा देने और युवाओं को एक वैकल्पिक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करने के लिए देश में पहली बार कोऑपरेटिव यूनिविर्सिटी की स्थापना की गई है। भारतीय सहकारिता आंदोलन के जनक और अमूल के संस्थापकों में शामिल त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। गुजरात के आणंद में स्थापित यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान है। इसी साल से यहां सहकारी प्रबंधन के तीन कोर्स शुरू हो चुके हैं, जबकि सहकारिता का शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाले पहले से देश में मौजूद विभिन्न संस्थानों को इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन देने का काम शुरू हो चुका है। इस यूनिवर्सिटी ने अभी तक सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 50 कोर्स चिन्हित किए हैं जिनके पाठ्यक्रम बनाने पर काम चल रहा है। सभी राज्यों एवं कोऑपरेटिव फेडरेशन से यूनिवर्सिटी ने कोर्स का सुझाव मांगा है। अगले सेशन से इन कोर्सों की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। इसके पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाए जा रहे हैं।

इसकी स्थापना से न केवल सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सहकारी क्षेत्र को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने में भी यह मदद करेगा। भारतीय सहकारी आंदोलन के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। यह संस्थान सहकारी शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे सहकारी

**व्यापक कानूनी और प्रशासनिक सुधारों सहित सहकारिता की सबसे निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाए जाने से न सिर्फ ग्रामीण आबादी को इसका फायदा मिल रहा है, बल्कि रोजगार और कारोबार के भी नए अवसर खुल रहे हैं।**

**नई नीति में वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान तीन गुना बढ़ाने, 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी क्षेत्र का सक्रिय सदस्य बनाने और सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।**

संस्थानों का कार्य अधिक पेशेवर, आधुनिक और प्रभावी हो सकेगा। यह युवाओं को एक वैकल्पिक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करेगा। यहां से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सहकारी संस्थाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।

## राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025

सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने और सहकारिता को विकसित भारत का सूत्रधार बनाने के उद्देश्य से नई सहकारिता नीति 24 जुलाई, 2025 से लागू हो गई है। इसमें हालांकि सभी के लिए भागीदारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन इसके केंद्र में गांव, कृषि, ग्रामीण, महिलाएं, दलित और आदिवासी हैं। यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि उनमें सहकारिता की भावना भी मजबूत होगी। सहकारिता नीति 2025 सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नीति सहकारिता को ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ के रूप में सशक्त बनाने के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को एक समावेशी और आत्मनिर्भर विकास मॉडल से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर एक रोडमैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का कहना है, 'सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाकर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना नई नीति का विजन है। जबकि पेशेवर, पारदर्शी, तकनीक से युक्त, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व सफल छोटी-छोटी सहकारी इकाइयों को बढ़ावा देना और प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित करना इसका मिशन है। नई नीति में वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान तीन गुना बढ़ाने, 50 करोड़ नागरिकों को सहकारी क्षेत्र का सक्रिय सदस्य बनाने और सहकारी समितियों की संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।' नई नीति में सहकारिता क्षेत्र के लिए तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के छह स्तंभ निर्धारित किए गए हैं जिनमें नींव का सशक्तीकरण, जीवंतता को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता को बढ़ावा और

पहुंच का विस्तार, नए क्षेत्रों में विस्तार और सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना शामिल है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की यह एक बड़ी उपलब्धि में शुमार है।

## सहकार टैक्सी

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में ही केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर ओला व उबर जैसी सुविधाओं वाली सहकार टैक्सी समिति का गठन किया गया है। शिक्षा के अलावा परिवहन क्षेत्र में भी सहकारिता के माध्यम से क्रांति लाने के उद्देश्य से सहकार टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर की गई है। इस साल के अंत तक दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में इसकी शुरुआत हो जाएगी जिसका बाद में अन्य शहरों में विस्तार होगा। मोबाइल ऐप आधारित इस टैक्सी सेवा के शुरू होने से न केवल ग्राहकों को विकल्प मिलेगा, बल्कि टैक्सी चालकों को सशक्त बनाकर सहकारी उद्यमिता को बढ़ावा देने और सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करने में भी यह मददगार साबित होगा। इसके लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम से एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी बनाई गई है। देश के परिवहन क्षेत्र के लिए यह परिवर्तनकारी कदम है।

देशभर की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने वाली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) इस सहकारी समिति की मुख्य प्रमोटर है, जबकि देश की प्रमुख सहकारी संस्थाएं अमूल, नैफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीईएल अन्य प्रमोटर हैं। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया है। देश की दिग्गज सहकारी संस्थाओं का समर्थन मिलने से सहकार टैक्सी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सहकारी टैक्सी सेवा के ऐप आधारित प्लेटफॉर्म का नाम 'सहकार' होगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक टैक्सी के अलावा दोपहिया, ई-रिक्शा और अन्य चार पहिया वाहन भी बुक कर सकेंगे। सहकार टैक्सी की सबसे बड़ी विशेषता इसका सहकारी ढांचा है, जिसमें टैक्सी चालक न केवल सेवा प्रदाता होंगे, बल्कि सहकारी समिति के सह-मालिक भी होंगे। यह मॉडल चालकों को निष्पक्ष लाभ वितरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर कार्यस्थितियों का अवसर प्रदान करेगा। सहकार टैक्सी को केवल लाभ

**सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया है।**

## एक पेड़ मां के नाम

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहकारी संस्थाओं की भूमिका अहम रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों के मद्देनजर 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर पूरे देश में पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं। सहकारी समितियां भी इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों के माध्यम से 3 करोड़ पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई है। सहकारिता में पैक्स से लेकर अपेक्स (शीर्ष) तक की संस्थाएं इस दिशा में पेड़ लगाने में सक्रिय हैं।

कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जाएगा, बल्कि यात्रियों से उचित किराया लिया जाएगा और लाभ का बड़ा हिस्सा ड्राइवरों में समान रूप से बांटा जाएगा। ड्राइवरों की सामाजिक सुरक्षा का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसका स्वामित्व और प्रबंधन पूर्ण रूप से इसके सदस्यों, यानी टैक्सी चालकों के हाथों में होगा। यह सहकारी मॉडल पारदर्शी और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देगा। इस पहल का मूल मंत्र 'सहकार से समृद्धि' है, जो सहकारी मूल्यों पर आधारित समावेशी और टिकाऊ परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करता है।

ऐप आधारित निजी क्षेत्र की टैक्सी सर्विस से इतर सहकार टैक्सी को सहकारिता की भावना से चलाया जाएगा। इसमें यात्रियों से उचित किराया लिया जाएगा, सरचार्ज और टिप जैसी वसूली नहीं होगी। शुरुआती चरण में लगभग 400-500 ड्राइवरों को इस सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। छह महीने की सेवा के बाद प्रत्येक ड्राइवर 100 रुपये के पांच शेयर खरीदकर सहकारी समिति के सदस्य बन सकेंगे। सहकार टैक्सी सर्विस के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। इस सर्विस के लिए इन शहरों में कॉल सेंटर खोले जाएंगे जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। आमतौर पर टैक्सी सर्विस और अन्य सर्विस के कॉल सेंटर मेट्रो शहरों में ही होते हैं, लेकिन सहकारी टैक्सी के मामले में ऐसा नहीं होगा।

**कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की द्वितीय अनुसूची में अधिसूचित किया गया है। यह अब राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक में तब्दील हो गया है। साथ ही यह अब ग्रामीण सहकारी बैंकों के फेडरेशन के रूप में भी काम करेगा और आरबीआई एवं सरकार के समक्ष इनका प्रतिनिधित्व करेगा।**

## कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया

सहकारी बैंकों का बड़ा व सघन नेटवर्क होने का बावजूद केंद्रीय स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, जिससे उनकी समस्याओं का निदान समय पर नहीं हो पाता था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और समाधान निकाला। कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की द्वितीय अनुसूची में अधिसूचित किया गया है। यह अब राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक में तब्दील हो गया है। साथ ही यह अब ग्रामीण सहकारी बैंकों के फेडरेशन के रूप में भी काम करेगा और आरबीआई एवं सरकार के समक्ष इनका प्रतिनिधित्व करेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अम्ब्रेला संगठन के रूप में तो नैफकब है लेकिन रूरल कोऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई अम्ब्रेला संगठन नहीं था। यह इस कमी को पूरी करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की उच्च-स्तरीय कृषि ऋण समीक्षा समिति की सिफारिश पर 1993 में इसकी स्थापना कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका काम सहकारी समितियों और अन्य बैंकों के बीच धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि-उद्योगों, मत्स्य पालन, डेयरी और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराना और सहकारी बैंकों को तरलता सहायता प्रदान करना रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी समर्थन प्रदान करता है, संस्थागत संरक्षण निधि का प्रबंधन करता है, वैश्विक एजेंसियों से संसाधन जुटाता है, प्रतिभूतियों का व्यापार करता है और भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनुसंधान, परामर्श, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करता है। अब यह ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करेगा।

## जीडीपी कमेटी

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इस बात का पता ही नहीं है कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कितनी हिस्सेदारी है। अभी तक यही होता रहा है कि जिस क्षेत्र में सहकारी समितियां काम कर रही हैं, उसे उसी क्षेत्र में गिना जाता रहा है। जैसे शुगर कोऑपरेटिव को एग्रीकल्चर क्षेत्र में, डेयरी कोऑपरेटिव को डेयरी एवं पशुपालन में, फिशरीज कोऑपरेटिव को मत्स्य पालन के क्षेत्र में शामिल किया जाता रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र की ताकत और क्षमताओं को सामने लाने के लिए जीडीपी कमेटी के गठन का फैसला किया जो यह पता लगाएगी कि जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र का योगदान कितना है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अपर सचिव रविंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी में लेबर, फाइनेंस, कोऑपरेटिव और संबद्ध मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं। यह कमेटी फ्रेमवर्क तैयार करेगी और उसके हिसाब से ऑडिट होगा। इस ऑडिट के बाद सहकारिता मंत्रालय के स्तर पर दूसरी कमेटी बनेगी जो जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र के योगदान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

## पैक्स गठन पर जोर

इन बड़ी पहल के अलावा भी इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय की ओर से कई अहम पहल की गई है। पांच वर्षों में दो लाख नए पैक्स बनाने की योजना के तहत 2025 में अब तक 36 हजार नए पैक्स का गठन हो चुका है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय हर तिमाही सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सभी सहकारी फेडरेशनों, नाबार्ड और कोऑपरेटिव बैंकों के साथ मिलकर सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन करता है। अभी तक ये वर्कशॉप मसूरी, गुवाहाटी, कच्छ, भुवनेश्वर, शिलांग और तिरुपति में आयोजित किए जा चुके हैं।

इसके लिए राज्यों के साथ समन्वय बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षा बैठकों को आयोजन किया जा रहा है।

इसके अलावा सरकार की योजनाओं की राष्ट्रीय एवं क्षेत्रवार समीक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर के ये वर्कशॉप चंडीगढ़, पटना और हैदराबाद में हो चुके हैं जिनमें पैक्स और अन्न भंडारण योजना पर जोर दिया गया। सहकारिता मंत्रालय के चार साल पूरे होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में 6 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरदार पटेल के नाम पर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव और देश की पहली नमक कोऑपरेटिव का गठन भी मंत्रालय की बड़ी पहल है। सरदार पटेल के नाम पर बनी कोऑपरेटिव पूरे देश में कारोबार कर सकेगी।

सहकारिता मंत्रालय ही नहीं, अन्य मंत्रालय भी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को सफल बनाने में अपना-अपना योगदान दे रहे हैं। इस दिशा में रेलवे ने अनूठी पहल करते हुए रेल टिकट पर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो लगा रही है और रेलवे स्टेशन पर सहकारिता के प्रति जागरूकता फैलाने वाले वीडियो चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी एमओयू किया गया है जिसके तहत देशभर के एयरपोर्ट्स पर सहकारिता संबंधी ग्राफिक्स और वीडियो चलाए जाते हैं।■

**केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अपर सचिव रविंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी में लेबर, फाइनेंस, कोऑपरेटिव और संबद्ध मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं। यह कमेटी फ्रेमवर्क तैयार करेगी और उसके हिसाब से ऑडिट होगा। इस ऑडिट के बाद सहकारिता मंत्रालय के स्तर पर दूसरी कमेटी बनेगी जो जीडीपी में सहकारिता क्षेत्र के योगदान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।**

# पैक्स बन रहे ग्रामीण सेवा वितरण केंद्र

पैक्स को पीएम किसान और 10 केंद्रीय योजनाओं के साथ किया जा रहा है एकीकृत

किसान एक ही जगह से उठा सकेंगे हर योजना का लाभ, प्रत्येक किसानों तक बढ़ेगी पैक्स की पहुंच

**युवा सहकार टीम**

'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने के लिए देश में सहकारी क्षेत्र के विकास और विस्तार की मुहिम तेज हो गई है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के चार वर्षों के दौरान सहकारिता को ग्रामीण भारत के आर्थिक नवोन्मेष का एक सशक्त माध्यम बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के 100 से अधिक बहुआयामी पहल किए गए हैं। इसी दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को पीएम किसान और अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ एकीकृत करने के कारगर कदम उठाए हैं। इन योजनाओं में कृषि, मत्स्य, डेयरी और अन्य मंत्रालयों की 10 लाभार्थी योजनाएं शामिल हैं जो ग्रामीण विकास और किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सरकार ने कई योजनाओं को समेकित कर ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप तैयार किया है। सहकारी समितियां अब किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक खुशहाली का एक मजबूत आधार बन रही हैं। गांव स्तरीय सहकारी ऋण समितियों में पारदर्शिता लाने के सरकार के प्रयासों से पैक्स का पारिस्थितिकी तंत्र बदल दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने नीतिगत सुधारों और डिजिटलीकरण के जरिए पैक्स में अस्पष्टता और पारदर्शिता की कमी को दूर किया है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पैक्स के डिजिटलीकरण ने पहले ही परिचालन को बदलना शुरू कर दिया है, जिससे सहकारी समितियां अब दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल मंच के माध्यम से काम कर रही हैं।

दरअसल, सरकार का मकसद पैक्स को ग्रामीण सेवा वितरण केंद्र के रूप में स्थापित करना है ताकि गांव के लोगों को कृषि, मत्स्य, डेयरी एवं उनसे जुड़ी अन्य लाभार्थी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गांव से बाहर न जाना पड़े। इससे पैक्स किसानों को ऋण, उर्वरक, बीज, दवाइयां और अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करने में सक्षम होंगे। ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में पैक्स की भूमिका, दक्षता एवं पारदर्शिता में वृद्धि होगी। कृषि और ग्रामीण विकास की योजनाओं को पैक्स से जोड़ने से पैक्स की पहुंच प्रत्येक किसान तक होगी।

पीएम किसान के साथ-साथ 10 अन्य केंद्रीय योजनाओं को पैक्स के साथ एकीकृत करने की पहल की गई है। इनमें कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन, बागवानी मिशन, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि और पीएम किसान संपदा योजना शामिल हैं। पैक्स को मजबूती देने वाली इन योजनाओं के अलावा सहकारिता मंत्रालय ने पहले से ही पैक्स को व्यावहारिक बनाने और ग्रामीण आबादी को सुविधाएं पहुंचाने की अन्य पहलें की हैं।

## कंप्यूटरीकरण से बेहतर वित्तीय प्रबंधन

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 30 जून, 2025 तक देश के कुल 2,69,230 ग्राम पंचायतों में से 2,51,872 पंचायतों में पैक्स मौजूद हैं। इनमें से 80 हजार पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है जिनमें से 63 हजार से ज्यादा पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से एक समान एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित मंच मिला है जिसने केंद्रीय परियोजनाओं को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पैक्स के जरिए पीएम-किसान, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके), ब्याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, पीडीएस आउटलेट, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल डीलरशिप, कस्टम हायरिंग, पीएम जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलना संभव हुआ है।

ईआरपी सक्षम सॉफ्टवेयर से ऑडिट पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है, जिससे बेहतर वित्तीय प्रबंधन संभव किया जा रहा है। इसके माध्यम से विविध व्यवसायों से जुड़कर पैक्स की वित्तीय स्थिरता में वृद्धि हो रही है। सभी राज्यों के पैक्स में मॉडल बायलॉज लागू होने के साथ ही पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण, एलपीजी वितरण, पीएमबीजेके, पीएमकेएसके और उचित मूल्य की दुकानें आदि 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई है। इससे पैक्स की आमदनी में सुधार हुआ है, जिसके चलते अल्पकालिक ऋण पर पैक्स की अत्यधिक निर्भरता कम हुई है। मॉडल बॉयलॉज में पैक्स के बेहतर प्रशासनिक मानदंडों, पारदर्शिता और समावेशी सदस्यता का भी प्रावधान किया गया है। इससे प्राथमिक सहकारी समितियों में युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान हो गया है।

## पैक्स बने किसान समृद्धि केंद्र

बहु-क्षेत्रीय योजना संपर्क के माध्यम से पैक्स को भारत सरकार की दर्जनों योजनाओं में सहभागी बनने के लिए सक्षम बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक, कीटनाशक और विभिन्न अन्य कृषि इनपुट उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 36,592 पैक्स को पीएमकेएसके में अपग्रेड किया जा चुका है। इसी तरह, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के रूप में पैक्स ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने लगे हैं। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए अब तक 47,918 पैक्स ने सीएससी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। स्थानीय स्तर पर इससे जहां रोजगार सृजित करने में मदद मिली है वहीं पैक्स की आमदनी में वृद्धि हो रही है।

## खोल रहे जनऔषधि केंद्र

ग्रामीण नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां सुलभ कराने के लिए पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। देशभर में 762 पैक्स इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करके जनऔषधि केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार सहकारिता मंत्रालय के इन प्रयासों ने पैक्स को विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण वितरक बना दिया है।

## कर रहे एलपीजी वितरण

ईंधन और एलपीजी वितरक के रूप में पैक्स को खुदरा ईंधन आउटलेट संचालित करने और एलपीजी वितरक के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। इससे पैक्स की आय बढ़ेगी और राजस्व आधार बढ़ेगा। इन सुधारों से पैक्स की आर्थिक गतिविधियों में विविधता आ रही है, इनका सशक्तीकरण हो रहा है और किसानों की अल्पकालिक ऋण पर निर्भरता कम हो रही है, जिससे समग्र ग्रामीण विकास संभव हो रहा है।■

**36,592**

**पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में अपग्रेडेड**

**47,918**

**पैक्स ने सीएससी के रूप में शुरू किया काम**

**सरकार का मकसद पैक्स को ग्रामीण सेवा वितरण केंद्र के रूप में स्थापित करना है ताकि गांव के लोगों को कृषि, मत्स्य, डेयरी एवं उनसे जुड़ी अन्य लाभार्थी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गांव से बाहर न जाना पड़े। इससे पैक्स किसानों को ऋण, उर्वरक, बीज, दवाइयां और अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करने में सक्षम होंगे।**

# युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए नया फ्रेमवर्क जरूरी

सहकारिता क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी जो युवा इससे जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर की पारिवारिक पृष्ठभूमि सहकारी क्षेत्र की रही है। ऐसे ही ऊर्जावान युवाओं में शुमार हैं हर्ष संघाणी जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) की यूथ कमेटी के प्रेसीडेंट चुने गए हैं। इस पद पर चुने जाने वाले वह पहले भारतीय हैं। आईसीए दुनिया के 130 देशों के सहकारी संगठनों का शीर्ष संगठन है। भारतीय सहकारी क्षेत्र में युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवाओं के लिए सहकारी क्षेत्र में कितने मौके और कितनी चुनौतियां हैं सहित तमाम मुद्दों पर **हर्ष संघाणी** से **अभिषेक राजा** और **नुरूल कुसैन** ने विस्तार से बातचीत की। पेश हैं उनके प्रमुख अंश।

**आईसीए यूथ कमेटी का प्रेसीडेंट बनने पर युवा सहकार की पूरी टीम की ओर से आपको बधाई?**

धन्यवाद।

**युवाओं के लिए सहकारी क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं?**

सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। नौकरी की तलाश में युवा भटकते रहते हैं। उन्हें नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने की जरूरत है। इसी सोच को लेकर भारतीय सहकारिता आगे बढ़ रही है। खासकर, जब से सहकारिता का अलग मंत्रालय बना है, तब से सरकार इसी विजन पर फोकस कर रही है। भारत में जब भी सहकारिता की बात होती है, तो तीन क्षेत्रों के बारे में ही ज्यादा बात होती है। बैंकिंग, डेयरी एवं पशुपालन और कृषि क्षेत्र के बारे में ही हम ज्यादा बात करते हैं। मगर भारत में अभी तक टेक कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा नहीं हुई है। इसी तरह, हेल्थ कोऑपरेटिव जो हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ी है, एजुकेशन जैसे कई ऐसे कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क हैं जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना है, तो भारत में नए फ्रेमवर्क को लाना पड़ेगा।

**त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना को आप कैसे देखते हैं?**

मैं इसे भारतीय सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण में एक बड़ा बदलाव आता हुआ देख रहा हूं। यूनिवर्सिटी की स्थापना से सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्कूल स्तर से ही कोऑपरेटिव की पढ़ाई का जो फैसला हुआ है उससे अगले 10-20 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कोई भी बच्चा जब स्कूल से ही कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ाई करके निकलेगा, तो उसे इस क्षेत्र की पहले से ही जानकारी होगी। अभी होता यह है कि युवाओं को इस क्षेत्र के बारे में कम जानकारी होती है। उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि इसमें कैसे आना चाहिए, इसके माध्यम से वह क्या-क्या कर सकता है और कैसे इसे अपना करियर बना सकता है। एजुकेशन क्षेत्र में भी कोऑपरेटिव्स पर फोकस शुरू हो गया है। सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक कोऑपरेटिव्स बनाए जा रहे हैं।

**क्या आपको लगता है कि युवाओं ने कोऑपरेटिव को करियर के रूप में देखना शुरू कर दिया है?**

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आईसीए के जो 130 सदस्य देश हैं उनमें से बहुत सारे युवा सदस्य आईसीए यूथ कमेटी से जुड़े हुए हैं। कई देशों के युवा अलग-अलग तरीकों से कोऑपरेटिव से जुड़ रहे हैं। कोई कंज्यूमर कोऑपरेशन से जुड़ा है, कोई एनिमल हसबैंड्री सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो कोई फाइनेंसिंग कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। भारत में कोऑपरेटिव से युवाओं को जोड़ने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जो कदम उठा रहे हैं उससे चीजें बदल रही हैं। युवा सहकारिता की तरफ मुड़ रहे हैं। सरकार की पहल का व्यापक असर अगले 5-10 साल में देखने को मिलेगा। भारत की बदौलत एशिया के सहकारिता क्षेत्र में भी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।

**आईसीए यूथ कमेटी का प्रेसीडेंट होने के नाते आप इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं या लाने को लेकर आपकी क्या तैयारी है?**

आईसीए यूथ कमेटी के सदस्य दुनिया के विभिन्न देशों से होते हैं। किसी कार्यक्रम या सेशन में सभी का एक समय एक साथ मिलना मुश्किल होता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने ग्लोबल यूथ कोऑपरेटिव लीडरशिप समिट करने का फैसला किया है। यह समिट अगले साल मार्च के अंत तक अप्रैल में हो सकता है। इसके लिए दो-तीन देशों के प्रधानमंत्रियों और युवा मामले के मंत्रियों से बातचीत चल रही है। इसके माध्यम से हम इंटर-जेनरेशनल डायलॉग शुरू करने वाले हैं। कोऑपरेटिव के सीनियर लीडर्स से युवा लीडर्स को जोड़कर उनके अनुभव से सीखने की यह शुरुआत है। इसके माध्यम से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीजें शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही नए-नए क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव्स हैं, एआई में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कोऑपरेटिव्स का एक थिंक टैंक बना रहे हैं जिसमें युवा आकर अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा।

**अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से भारतीय सहकारिता को कितना फायदा हुआ है?**

भारत एक ऐसा देश है जहां पहले से सहकारिता का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान सहकारिता को लेकर देश के लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कोऑपरेटिव्स से अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होता है, इससे हमारे गांवों में कैसे आर्थिक रूप से फायदा होता है, ये सारी चीजें लोग समझने लगे हैं। मेरे गुरु मुकुंद राव जी देवकर ने मुझे एक सुझाव दिया था कि क्यों न हम कोऑपरेटिव्स को ऐसा माध्यम बनाएं जो न बहुत पूंजीवादी हो और न समाजवादी हो, बल्कि ये दोनों के बीच में हो। इस बारे में हम लोग सोच रहे हैं और इसे बाकी लोगों को भी समझाना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष से लोगों को समझाना और जागरूक करना बहुत आसान हो गया है। इसकी वजह से घर-घर में सहकारिता को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है।

**आप केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। उन्होंने आपको कोई सुझाव दिया कि युवाओं को आगे कैसे बढ़ाना है?**

उन्होंने बहुत समर्थन दिया है। उन्होंने सुझाव तो बहुत सारे दिए हैं। मैंने भी उनसे बहुत सारी मांग की है। मुझे पता है कि उन मांगों पर वह अवश्य ध्यान देंगे और उन्हें पूरी करेंगे। उनके समर्थन से प्रेरणा मिलती है। युवाओं को प्रेरणा और समर्थन ही चाहिए। अमित शाह जी ने जो प्रेरणा दी है और जो समर्थन दिया है उससे ऐसा लगता है कि आगे का भविष्य युवा और सहकारिता दोनों के लिए बहुत मजबूत है।■

# कोऑपरेटिव्स को वैश्विक बाजारों से जोड़ रही एनसीईएल

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लिए दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का रखा लक्ष्य

एनसीईएल के जरिये ही निर्यात करने का सहकारी संस्थानों को निर्देश

5,403 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 13.49 लाख टन से अधिक कृषि वस्तुओं का विश्व स्तर पर 28 देशों में किया निर्यात

चावल, ताजा लाल प्याज, चीनी, शिशु आहार, प्रोसेस्ड फूड, मसाले और चाय सहित कृषि वस्तुओं का एक्सपोर्ट

वर्ष 2024-25 में 4,283 करोड़ रुपये के कारोबार से हासिल किया 122 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

11,000 से अधिक सहकारी समितियों को दी सदस्यता

**युवा सहकार टीम**

'सहकारिता को देश की अर्थव्यवस्था की औपचारिक रीढ़ बनाने के क्रम में सरकार इस क्षेत्र से होने वाले समस्त निर्यात की जिम्मेदारी बहु-राज्यीय सहकारी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) को देने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों ही केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को सलाह दी है कि वे अपना निर्यात इसी कंपनी के माध्यम से करें। यह शीर्ष सहकारी संस्था किसानों, सहकारी समितियों और ग्रामीण उत्पादकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की एक दूरदर्शी पहल है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि एनसीईएल का उद्देश्य विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है ताकि किसानों का व्यापक बाजारों तक पहुंच बने

और उसका लाभ उन्हें मिल सके। निर्यात में रुचि रखने वाली प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन रही हैं। निर्यात बाजारों से संपर्क स्थापित करके एनसीईएल सहकारी समितियों को मजबूती देने और उन्हें जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के साथ ही कृषि वस्तुओं के लिए नए बाजारों की खोज करने के क्षेत्र में समर्पित होकर कार्य कर रही है। किसानों को निर्यात बाजारों से जोड़ने, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों का समाधान करने, कृषि वस्तुओं के लिए निर्यात प्रमाणन हासिल करने और सुचारू रसद सुनिश्चित करने की दिशा में एनसीईएल अहम योगदान कर रही है। अब एनसीईएल भारत की सहकारी समितियों का वैश्विक चेहरा बनने के लिए तैयार है। यह पहल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ सहकारिता आंदोलन में नई ऊर्जा और अवसरों का संचार कर रही है।

एनसीईएल के माध्यम से भारतीय किसान अब अपनी कृषि उपज का निर्यात सीधे वैश्विक दुनिया और विकसित देशों तक कर रहे हैं। इसका लक्ष्य बेहतर मांग और उचित मूल्य को देखते हुए भारतीय सहकारी समितियों से अधिशेष उपज को वैश्विक बाजारों में ले जाना है। यह खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमाणन और मार्केटिंग को संभालकर निर्यात में मदद करता है। इसके साथ-साथ एनसीईएल वित्तीय व्यवस्था करता है, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है, कौशल निर्माण में मदद करता है, बाजार की जानकारी विकसित करता है और सदस्यों को सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। इस तरह यह सहकारी समितियों की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनकी मौजूदगी का विस्तार करता है। दरअसल, एनसीईएल के जरिये सहकारी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया है, जिससे स्थानीय सहकारी कृषि उपज और कौशल को दुनिया भर में बाजार खोजने में सक्षम बनने की शक्ति मिली है। इस तरह से सहकारी उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़कर एनसीईएल ने 'मेक इन इंडिया' की विचारधारा को मजबूत किया है, बाजार संबंधों को समृद्ध किया है और सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए हैं।

## दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य

अमित शाह का कहना है कि सहकारिता देश के ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की कुंजी हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में, जहां समानता के साथ विकास की संभावना है, सहकारी समितियां विशेष रूप से सहायक हैं। उन्होंने एनसीईएल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सहकारी समितियों को वैश्विक स्तर पर सोचने और स्थानीय स्तर पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सहकारिता

**एनसीईएल के माध्यम से भारतीय किसान अब अपनी कृषि उपज का निर्यात सीधे वैश्विक दुनिया और विकसित देशों तक कर रहे हैं। इसका लक्ष्य बेहतर मांग और उचित मूल्य को देखते हुए भारतीय सहकारी समितियों से अधिशेष उपज को वैश्विक बाजारों में ले जाना है। यह खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रमाणन और मार्केटिंग को संभालकर निर्यात में मदद करता है।**

> **एनसीईएल ने सहकारी-आधारित कृषि निर्यात को मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, गुणवत्ता अनुपालन, बुनियादी ढांचे का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी शामिल होगी।**

मंत्रालय ने पहल किया है। इससे दुनिया भर में कृषि, बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन, पशुधन, मत्स्य पालन, चीनी, मसाले, जैविक उत्पाद, उर्वरक, हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा, चाय व कॉफी, लघु वनोपज, आयुर्वेदिक व हर्बल औषधियां, प्रोसेस्ड फूड और चमड़ा आदि क्षेत्रों में निर्यात के जरिये किसानों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा। अमित शाह ने निर्देश दिया है कि सभी सहकारी संस्थानों का निर्यात एनसीईएल के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि करीब 20-30 हजार करोड़ रुपये का कारोबार और शुद्ध लाभ सहकारी समितियों में वापस आ सके। उन्होंने दालों के आयात के लिए अफ्रीका और म्यांमार में एनसीईएल कार्यालय स्थापित करने और सहकारी सदस्यों को वैश्विक मांग को समझने और उनकी आपूर्ति क्षमता प्रदर्शित करने में मदद करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट विकसित करने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने सहकारी समितियों की शक्तियों का लाभ उठाने और उन्हें सफल एवं जीवंत व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया।

## सहकारी उपज को वैश्विक बाजारों में पहुंचा रही एनसीईएल

एनसीईएल निर्यात बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, कुप्रथाओं, बुनियादी ढांचे की कमी और मानकीकरण जैसी समस्याओं का समाधान करके सहकारी कृषि उत्पादों को विश्व के लच्छित ग्राहकों तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है। महज दो सालों में एनसीईएल ने लाखों टन उपज का निर्यात किया है और अपनी सदस्यता व्यापक ढंग से बढ़ाते हुए उन सदस्यों के साथ लाभ साझा किया है। देश की इस शीर्ष सहकारी निर्यात समिति ने 28 देशों में अपने निर्यात का विस्तार किया है, जिनमें बासमती और गैर-बासमती चावल, समुद्री उत्पाद (विशेष रूप से झींगा), मोटे अनाज, गेहूं, फल और सब्जियां, पशु उत्पाद, मसाले और वृक्षारोपण उत्पाद प्रमुख हैं। एनसीईएल ने जहां वर्ष 2023-24 के दौरान अपने सदस्य सहकारी समितियों को 20 प्रतिशत लाभांश का भुगतान किया, वहीं वर्ष 2024-25 के लिए 4,283 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ 122 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हासिल किया है। ये उपलब्धियां भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक ताकत में बदलने की एनसीईएल की क्षमता को दर्शाती हैं।

इस दौरान एनसीईएल ने सेनेगल, इंडोनेशिया और नेपाल के 61 आयातकों के साथ रणनीतिक समझौतों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एनसीईएल ने

अहम परिणाम देते हुए अगस्त 2025 तक 11,034 सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की है, जिनमें 10,793 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), 216 तहसील व जिला स्तरीय सहकारी समितियां, 10 बहु-राज्य सहकारी सोसायटी, 10 राज्य स्तरीय सहकारिता सोसायटी और पांच प्रवर्तक सहकारी समितियां व संगठन शामिल हैं। इस दौरान एनसीईएल के माध्यम से 13.49 लाख टन से अधिक चावल, ताजा लाल प्याज, चीनी, शिशु आहार, प्रोसेस्ड फूड, मसाले और चाय सहित कृषि वस्तुओं का निर्यात हो चुका है, जिसका मूल्य 5,403 करोड़ रुपये से भी अधिक है। इसी वर्ष संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि एनसीईएल को 16 देशों को 14,92,800 टन गैर-बासमती सफेद चावल, पांच देशों को 8,98,804 टन टूटे चावल, एक देश को 14,184 टन गेहूं, 5,326 टन गेहूं का आटा, 15,226 टन मैदा एवं सूजी और दो देशों को 50,000 टन चीनी निर्यात करने जा रहा है। इसके साथ ही एनसीईएल को 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 2,581 सदस्यता आवेदन भी मिले हैं।

## बाजार मौजूदगी का विस्तार की रणनीति

एनसीईएल निर्यात बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपना रहा है। इसने राज्य नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और पैक्स के साथ जुड़ने के लिए व्यावसायिक योजनाएं तैयार की हैं। एनसीईएल ने सहकारी-आधारित कृषि निर्यात को मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, गुणवत्ता अनुपालन, बुनियादी ढांचे का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी शामिल होगी। यह अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, बाजार स्थिति, डेटा-संचालित बाजार बुद्धिमत्ता और कमोडिटी-विशिष्ट निर्यात रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

इस दिशा में एक अहम पहल करते हुए किसानों और सहकारी समितियों को निर्यात हेतु तैयार करने के लिए एक कमोडिटी सेमिनार श्रृंखला शुरू की गई, जिसका पहला आयोजन जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश में हुआ। कमोडिटी विशिष्ट रणनीतियों को डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसियों, रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी कार्यालयों और अन्य हितधारकों के साथ 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके साथ ही, सोशल मीडिया, मार्केटिंग टूल और जागरूकता अभियानों के जरिए ब्रांडिंग और डिजिटल आउटरीच को मजबूत किया गया। विशेष रूप से पैक्स से सदस्यता बढ़ाने के लिए एक 'बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग' (बीपीओ) आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया।■

# डेयरी सेक्टर में बनेंगे 75 हजार कोऑपरेटिव्स

श्वेत क्रांति 2.0 में होगी इनकी स्थापना, 46 हजार डेयरी कोऑपरेटिव्स को किया जाएगा मजबूत- अमित शाह

साबर डेयरी ने हरियाणा के रोहतक में 350 करोड़ रुपये की लागत से बनाया देश का सबसे बड़ा दही, दूध और मिठाई बनाने का प्लांट

रोजाना 150 टन दही, 10 टन योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और 10 हजार किलो मिठाई बनाने की है क्षमता

**युवा सहकार टीम**

भारत पिछले कई वर्षों से दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक देश है। दुनिया के कुल दूध उत्पादन का यहां करीब 25 फीसदी उत्पादन होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में भारत का वार्षिक दूध 23.9 करोड़ टन से अधिक था जिसे 2030 तक बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बावजूद वैश्विक निर्यात में दुग्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम है क्योंकि यहां उत्पादित दूध की खपत घरेलू स्तर पर ही हो जाती है। अब सरकार का फोकस पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर निर्यात में दुग्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने पर है जिसमें सहकारी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरूआत की गई है जिसके तहत 75 हजार से अधिक डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी और 46 हजार डेयरी समितियों को मजबूत किया जाएगा। इसके माध्यम से अगले पांच वर्षों में देश के कुल दूध उत्पादन में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण करते हुए कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 के तहत आने वाले वर्षों में देशभर में 75 हजार से अधिक डेयरी समितियों की स्थापना होगी। साथ ही सरकार 46 हजार डेयरी कोऑपरेटिव को मजबूत भी करेगी। वर्तमान में देश की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 660 लाख लीटर प्रतिदिन है जिसे वर्ष 2028-29 तक बढ़ाकर 1,000 लाख लीटर तक करने का लक्ष्य है। एक साल में ही लगभग 33 हजार

कोऑपरेटिव्स को पंजीकृत कर दिया गया है।

भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70 प्रतिशत की क्षमता से बढ़ा है। यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर है। 2014-15 में भारत में दूध देने वाले पशुओं की संख्या 8.6 करोड़ थी जो अब बढ़कर 11.2 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार, दुग्ध उत्पादन 14.6 करोड़ टन से बढ़कर 23.9 करोड़ टन हो गया है। देसी नस्ल की गाय के दूध का उत्पादन 2.9 करोड़ टन से बढ़कर 5 करोड़ टन तक पहुंच गया है। अमित शाह ने कहा कि आज भारत के लगभग 8 करोड़ किसान डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 124 ग्राम से बढ़ाकर 471 ग्राम करने का काम देश के किसानों ने किया है। पिछले 11 साल में भारत के डेयरी सेक्टर में कई बदलाव हुए हैं जिससे किसान समृद्ध हुए हैं। अब वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

रोहतक में निर्मित साबर डेयरी प्लांट पर 350 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह दही, छाछ और योगर्ट बनाने का देश का सबसे बड़ा प्लांट है। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा से ही दिल्ली-एनसीआर की दुग्ध उत्पादों की जरूरत पूरी होगी। साबर डेयरी ने गुजरात के साबरकांठा जिले से शुरूआत कर 9 राज्यों के दुग्ध उत्पादकों के लिए बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। साबर प्लांट में प्रतिदिन 150 टन दही, 10 टन योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और प्रतिदिन 10 हजार किलो मिठाई बनेंगे। इससे किसानों की समृद्धि का रास्ता खुलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की सेवा कर रही है। अमित शाह के अनुसार, अमूल के नेतृत्व में गुजरात में आधुनिक प्रजनन तकनीकोंझ्र भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण- पर काफी वैज्ञानिक काम हुआ है। ये दोनों तकनीकें हरियाणा के पशुपालकों को भी उपलब्ध होंगी।

डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने तीन

राष्ट्रीय सहकारी समितियां बनाईं हैं। एक समिति पशु आहार के उत्पादन पर फोकस करेगी, दूसरी गोबर का प्रबंधन करेगी और बायो गैस उत्पादन को बढ़ावा देगी। तीसरी समिति मृत पशुओं के अवशेषों का प्रबंधन करेगी जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने डेयरी सेक्टर को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय कृत्रिम गभार्धान और राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण जैसे कार्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी बनाया है।

अमित शाह ने कहा कि सरकार डेयरी संयंत्र के निर्माण की दृष्टि से भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए डेयरी संयंत्र निर्माण और उससे जुड़े रिसर्च एवं डेवलपमेंट के सेक्टर में तीन गुना तेजी लाकर डेयरी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।■

**वर्तमान में देश की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 660 लाख लीटर प्रतिदिन है जिसे वर्ष 2028-29 तक बढ़ाकर 1,000 लाख लीटर तक करने का लक्ष्य है। भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70 प्रतिशत की क्षमता से बढ़ा है। यह विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर है।**

# एनवाईसीएस ने जरूरतमंद बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री

**युवा सहकार टीम**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिवस को देशभर में 'स्वच्छता पखवाड़ा' के रूप में मनाया गया। इस क्रम में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) की चंडीगढ़ शाखा ने सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए रामदरबार कॉलोनी में एक विशेष सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों को कॉपियां, किताबें, पेन-पेंसिल और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान की गई, ताकि वे अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की कमी महसूस न करें। इसके अतिरिक्त, स्थानीय सफाई कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए ग्लव्स और मास्क वितरित किए गए।

इस पहल का उद्देश्य न केवल स्वच्छता अभियान को गति देना था, बल्कि उन सफाई कर्मियों का सम्मान करना भी था, जो प्रतिदिन समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एनवाईसीएस के राष्ट्रीय निदेशक देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को छोटी-छोटी प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर शिक्षा की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'शिक्षा ही वह साधन है, जो जीवन में वास्तविक प्रगति और आत्मनिर्भरता की राह खोलता है। यदि किसी भी बच्चे को पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, तो एनवाईसीएस हरसंभव सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। इस तरह के कार्यक्रम समाज में जागरूकता, सहयोग और सशक्तीकरण की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।'

> **इस तरह के कार्यक्रम समाज में जागरूकता, सहयोग और सशक्तीकरण की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।**

उन्होंने एनवाईसीएस की चंडीगढ़ शाखा की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए स्थानीय नागरिकों से भी शिक्षा और स्वच्छता जैसे अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में एनवाईसीएस चंडीगढ़ शाखा के निदेशक सहदेव गर्ग, आशा, विकास राणा, कार्यालय कर्मी सुरेश और संजीव, समाजसेवी वरिंदर जेडी, राजिंदर मकवाना सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी और स्थानीय लोग शामिल हुए।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बच्चों और सफाई कर्मियों के चेहरों पर मुस्कान देखकर कार्यक्रम को सार्थक बताया और यह संकल्प लिया कि वे शिक्षा, स्वच्छता और समाजसेवा जैसे कार्यों में निरंतर सहयोग करेंगे।■

# एनवाईसीएस के रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़

**युवा सहकार टीम**

एनवाईसीएस की पाटन (गुजरात) शाखा ने पिछले दिनों आशा एकेडमी में रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में आस-पास के 25 गांवों से सैकड़ों युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा अलग-अलग कंपनियों में आवेदन किया। यह आयोजन युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उनके करियर निर्माण में सहयोग देने के उद्देश्य से किया गया।

इस रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण योजनाओं और करियर मार्गदर्शन सत्रों का आयोजन किया गया। इससे युवाओं को न सिर्फ नौकरियों की जानकारी मिली, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। इस रोजगार मेले का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं तक रोजगार की पहुंच को सुलभ बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ना था। यह मेला इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

इस अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित अतिथि उपस्थित रहे जिनमें प्रमुख रूप से एनवाईसीएस के महाप्रबंधक अभिषेक कुमार,

राजस्थान के प्रतिनिधि राजेश गुर्जर, आशा एकेडमी के निदेशक निश्चल यादव, सरपंच लाल सिंह शेखावत, महिपाल यादव (आशा देवी पी.जी. कॉलेज के व्यवस्थापक), प्राचार्य सुखवीर यादव, भाजपा नेता रामसिंह दासाला, प्रदीप यादव (कालामेडा)

और मनीष शर्मा (हसामपुर) विशेष रूप से मौजूद रहे। ■

# अन्न भंडारण से ग्रामीण युवा होने लगे सशक्त

29,000 पैक्स में बनाए जा रहे हैं अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम

गोदाम बनने से ग्रमीण स्तर पर पैदा हो रहे रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर

1 लाख करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है 7 करोड़ टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता

**युवा सहकार टीम**

अनाज की बबार्दी रोकने और कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए केंद्र सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है। एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पांच वर्ष में कुल सात करोड़ टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है। सहकारिता की निचली इकाई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गोदाम बना रही है। इस योजना से न सिर्फ गांवों में अनाज भंडारण को बढ़ावा मिलने लगा है, बल्कि यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलने लगा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 पैक्स से शुरू हुई यह योजना अब 29,000 पैक्स तक बढ़ाई जा चुकी है। इन पैक्सों में गोदाम निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में है। पायलट प्रोजेक्ट वाले पैक्स के गोदामों में अन्न भंडारण तो पहले ही शुरू हो चुका है, बाकी पैक्स के गोदामों में कुछ में अनाजों का भंडारण शुरू हो चुका है, तो कुछ निमार्णाधीन हैं।

केंद्रीय सहकारिता सचिव आशीष कुमार भूटानी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित सहकारिता मंत्रालय की कार्यशाला में इस बात की जानकारी दी। इस कार्यशाला में अन्न भंडारण योजना पर एक सत्र रखा गया था। इस सत्र में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही व्यवसाय विविधीकरण के माध्यम से गोदामों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने, भूमि की उपलब्धता, सहकारी शक्ति और मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर पैक्स का मानचित्रण करने और स्थायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने पर प्रकाश डाला गया। सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के बारे में आयोजित इस दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधि, सचिव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार

(आरसीएस) और सहकारी क्षेत्र के प्रमुख हितधारक शामिल हुए।

भंडारण के दौरान अनाज की होने वाली क्षति रोकने में भी यह योजना मददगार है। गांव में गोदाम बनने से उनका रखरखाव, प्रबंधन करने जैसे प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा अनाजों की ढुलाई सहित अप्रत्यक्ष रोजगार के अन्य अवसर पैदा हो रहे हैं जो उस गांव और पंचायत के युवाओं के लिए ही उपलब्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही कृषि और उससे संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी निर्माण हो रहा जिससे भी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इनमें कस्टम हायरिंग सेंटर, अनाज खरीद केंद्र, अनाज खरीद के बाद उसके लिए प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कारोबार के विविधीकरण से पैक्स आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।

ग्रामीण गोदामों के निर्माण के पहले चरण में देश के सभी ब्लॉकों में गोदाम बनाए जा रहे हैं। इस हिसाब से तकरीबन 50,000 टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण पहले चरण में होने का अनुमान है। इस योजना में नई फ्लेक्सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अनाज की जरूरत के हिसाब से 50, 100, 250, 500 और 750 टन क्षमता के साइलोज (आधुनिक तकनीक से स्टील के गोदाम) और सामान्य गोदाम बनाए जा रहे हैं। पैक्स के बनाए इन गोदामों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य प्राइवेट एजेंसियों को भंडारण के लिए किराये पर दिया जा रहा है। इससे पैक्स की आमदनी बढ़ रही है। यहीं से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पैक्स के खरीदे अनाज की बिक्री भी हो रही है। इन गोदामों में अनाज की प्रोसेसिंग की सुविधा भी तैयार की जा रही है, जिससे उपज को मूल्यवर्धित करके बेचा जा सकेगा। ग्राम स्तर पर बनाए जा रहे छोटे गोदामों से किसानों को लाभ मिलने लगा है। इसके अलावा, सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाने का खर्च भी कम होने लगा है। अभी तक होता यह रहा है कि गांव से अनाज शहर के गोदामों तक पहुंचता है और वहां से फिर गांव की राशन दुकानों तक पहुंचाया जाता है। इससे माल ढुलाई का खर्च दोगुना हो जाता है। गांव में गोदाम बनने से अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाने के खर्च में काफी कमी आई है।

डॉ. भूटानी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर कार्यशाला में प्रकाश डालते हुए कहा कि आज सहकारिता कृषि और ऋण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा, सेवाओं और मूल्य श्रृंखला एकीकरण जैसे क्षेत्रों में भी फैल गई हैं। सहकारी समितियां जन-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार हो रही हैं। इस कार्यशाला में पैक्स संचालन के पूर्ण डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने, पैक्स कर्मचारियों और सदस्यों की डिजिटल क्षमता का निर्माण करने और पैक्स को कृषि इनपुट, ऋण, खरीद और भंडारण जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाली वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया। इस दौरान नाबार्ड की ओर से परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर विकास, हार्डवेयर खरीद और क्षमता निर्माण सहायता पर भी अपडेट प्रस्तुत किए गए।

इस कार्यशाला में सभी पंचायतों और गांवों में दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन तथा उनके सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा हुई। इसमें नए सहकारी संगठन के लिए संभावित जिलों और प्रखंडों की पहचान करने, व्यवसाय सक्रियता और विविधीकरण के माध्यम से मौजूदा समितियों को मजबूत करने और ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला और समीक्षा बैठक के दूसरे दिन सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक सत्र हुआ, जिसका विषय ह्वव्यावसायिक विविधीकरण के माध्यम से पैक्स के क्षितिज का विस्तारह्व था। इसमें प्रमुख पहलों पर चर्चा हुई।■

**कृषि और उससे संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी निर्माण हो रहा जिससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इनमें कस्टम हायरिंग सेंटर, अनाज खरीद केंद्र, अनाज खरीद के बाद उसकी प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कारोबार के विविधीकरण से पैक्स आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।**

# शुभमन गिल को वन डे की भी कप्तानी

**शुभमन बतौर कप्तान और बल्लेबाज रोहित और विराट का आदर्श मिश्रण हैं। गिल ने अपने आदर्श विराट कोहली की तरह धैर्य, जोश और गियर बदलने की क्षमता दिखाई है, वह अब उनका महज अक्स नहीं, बल्कि उनकी तरह वह कामयाबियों की बुलंदियां छूने की दिशा में बढ़ रहे हैं।**

**सत्येन्द्र पाल सिंह**

रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल की वन डे क्रिकेट कप्तान के रूप में भी नियुक्ति भारतीय क्रिकेट के नए युग का आगाज है। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद 25 बरस के शुभमन गिल ने चंद महीने पहले ही इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी। इसके तुरंत बाद उन्हें सूर्य कुमार यादव की अगुआई वाली टी20 टीम का उपकप्तान बना दिया गया, जिसने पिछले महीने यूएई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को फाइनल सहित तीन बार हराकर एशिया कप जीता। गिल अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी संभालने की ओर बढ़ चुके हैं। भारत और दुनिया के सर्वकालीन महानतम सलामी बल्लेबाज में से एक सुनील गावसकर ने भी उन्हें टेस्ट के साथ वन डे टीम की कप्तानी सौंपे जाने को 2027 में होने वाले आईसीसी वन डे क्रिकेट विश्व कप के मद्देनजर एक दूरदर्शी कदम बताया है। गावसकर का भी मानना है कि वह भविष्य के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजित आगरकर का यह बयान कि तीनों फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना बहुत मुश्किल है, इस बात की बहुत हद तक पुष्टि करता है।

गिल को वन डे टीम की भी कप्तानी सौंपा जाना एक वर्ग को भा नहीं रहा है। इस वर्ग का एक दर्द यह है कि रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई और दूसरा यह है कि श्रेयस अय्यर को इस पद के लिए नजरअंदाज कर दिया गया। आलोचकों का तर्क है कि बहुत सारी जिम्मेदारी सौंपा जाना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज खत्म होने के बाद उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तीन वन डे की सीरीज और उसके बाद पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। ये दोनों सीरीज 8 नवंबर तक चलेगी। स्वदेश वापस लौटने पर भारतीय टीम मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे पहले दो टेस्ट की सीरीज, फिर तीन वन डे मैच और 19 दिसंबर तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। इस साल के आखिर तक टीम पूरी तरह व्यस्त रहेगी। अजित आगरकर ने शुभमन गिल के इस तरह लगातार खेलने के पक्ष में उन्हें नौजवान बताते हुए इस तरह की किसी भी आशंका को खारिज कर दिया।

आगरकर ने गिल को ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ तीन वन डे मैचों की सीरीज खेलने वाली भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त

करने की बाबत कहा कि यह फैसला अक्टूबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामिबिया में होने वाले आईसीसी वन डे क्रिकेट विश्व कप की दीर्घकालिक योजना को ध्यान में रख कर लिया गया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय चयनकर्ता चाहते हैं कि गिल विश्व कप से पहले भारत के कप्तान के तौर पर पूरी तरह स्थापित हो जाएं।

टेस्ट और टी20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके और करीब दो दशक तक क्रिकेट में भारत का परचम शान से लहराने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ वन डे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब उम्र दोनों के हक में है ही नहीं। भारत को 2027 के क्रिकेट विश्व कप से पहले मात्र दस वन डे अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेलने हैं। हालांकि, भारत इसके मद्देनजर कुछेक वन डे सीरीज खेलने की बाबत जरूर सोच सकता है। रोहित और विराट अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय वन डे करियर को और आगे बढ़ाना चाहते है तो दोनों को घरेलू क्रिकेट में अपने-अपने राज्य के लिए खेलना होगा। मुख्य चयनकर्ता आगरकर यह साफ कर चुके हैं कि इसको लेकर कोई ढील नहीं दी जाएगी। आगरकर ने कहा, 'रोहित और विराट जब भी उपलब्ध होंगे दोनों को घरेलू क्रिकेट में खेलना ही होगा क्योंकि इसमें खेल कर आप खुद को फिट रख सकते हैं।' विराट कोहली ने 2013 के बाद से घरेलू वन डे विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेली है, जबकि रोहित शर्मा इसमें आखिरी बार 2018 में मुंबई के लिए खेले थे। इस साल विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा।

दोनों बेशक जानते हैं कि उनके क्रिकेट करियर की सांझ बहुत तेजी से दस्तक दे रही है। रोहित शर्मा अगले वन डे विश्व कप तक 40 बरस के और विराट कोहली 38 बरस के हो जाएंगे। इसे भारत की खुशकिस्मती कहें या क्रिकेट की कड़वी हकीकत कि टेस्ट और टी20 दोनों में, खासतौर पर टेस्ट में खुद बतौर कप्तान और बल्लेबाज शुभमन गिल और टी20 में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवा तुर्कों ने बल्ले से धमाल कर रोहित और विराट की इन दोनों फॉर्मेट में कमी कतई अखरने नहीं दी। आलम यह है कि यशस्वी जायसवाल जैसा नौजवान बल्लेबाज जिसने टेस्ट और टी20 दोनों में धमाल मचाया, वन डे की 15 सदस्यीय टीम में स्थान पाने की बाट जो रहा है। ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली वन डे टीम में जगह नहीं पा सके। संकेत साफ है कि उम्र रोहित और विराट दोनों के साथ नहीं है। इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने जाने के बावजूद वन डे विश्व कप के मद्देनजर चयनकर्ता अभी असमंजस में हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इन दोनों को टीम में जरूर शामिल किया गया है, लेकिन एक साफ संदेश भी दे दिया गया है कि एकादश में दोनों की जगह तभी पक्की होगी जब उनके बल्ले से रन बरसेंगे। रोहित और विराट घरेलू क्रिकेट में नहीं खेल रहे। ऐसे में यदि दोनों बल्ले से भारत के लिए रंगत नहीं दिखाएंगे तो फिर उन्हें एकादश में शामिल किए जाने पर सवाल उठते देर नहीं लगेगी। विराट कोहली तो अब पत्नी अनुष्का के साथ इंग्लैंड में रह रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि वह घरेलू क्रिकेट में अपने राज्य दिल्ली के लिए खेलने के लिए कितना उपलब्ध रहेंगे? आगरकर कहते हैं, 'रोहित और विराट अब केवल वन डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही खेल रहे हैं और इसीलिए दोनों को वन डे टीम में चुना गया है।'

शुभमन गिल चयनकर्ताओं के लिए दीर्घावधि योजना का हिस्सा हैं, लेकिन रोहित और विराट के लिए यह बात विश्वास से नहीं कही जा सकती है। सच तो यह है कि शुभमन बतौर कप्तान और बल्लेबाज रोहित और विराट का आदर्श मिश्रण हैं। गिल ने जिस तरह अपने आदर्श विराट कोहली की तरह धैर्य, जोश और गियर बदलने की क्षमता दिखाई है, वह अब उनका महज अक्स नहीं, बल्कि उनकी तरह कामयाबियों की ऐसी बुलंदियां चूमेंगे, जिस पर हर भारतीय गर्व करेगा।■

**(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)**

**यह फैसला अक्टूबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामिबिया में होने वाले आईसीसी वन डे क्रिकेट विश्व कप की दीर्घकालिक योजना को ध्यान में रख कर लिया गया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय चयनकर्ता चाहते हैं कि गिल वन डे विश्व कप से पहले भारत के कप्तान के तौर पर पूरी तरह स्थापित हो जाएं।**

# सोच बदली तो बदल गई जिंदगी

**युवा सहकार टीम**

दिल्ली निवासी शिवानी एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ी जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पिता इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और परिवार एक रूढ़िवादी परिवेश से था जिसमें लड़कियों को बाहर निकल कर काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था।

एक दिन शिवानी ने नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) की टीम को अपने इलाके में कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में पैम्फलेट बांटते देखा। अधिक जानने की उत्सुकता में उसने भी एक पैम्फलेट लिया और पाया कि एनवाईसीएस आईजीएल सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत सेल्फ एम्प्लॉयड टेलरिंग, सीसीटीवी और ब्यूटी वेलनेस में निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। ब्यूटी वेलनेस कार्यक्रम उसकी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुरूप था, लेकिन अपने परिवार को इसमें दाखिला लेने के लिए राजी करना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी।

उसने अपनी चिंता एनवाईसीएस की ब्यूटी प्रशिक्षक से साझा की जिन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके माता-पिता से बात करेंगी। एनवाईसीएस की टीम ने उसके पिता से संपर्क किया और बताया कि कैसे यह प्रशिक्षण उन्हें सशक्त बनाएगा और कैसे शिवानी परिवार का आर्थिक सहयोग कर सकती है। जिम्मेदारी सिर्फ बेटों पर ही नहीं होती, बेटियां भी अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ी हो सकती हैं।

एनवाईसीएस की टीम के समझाने पर आखिरकार शिवानी का परिवार मान गया। शिवानी ने न केवल कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि प्रशिक्षण के बाद काम भी शुरू किया। शिवानी के लिए यह सफर सिर्फ रोजगार योग्य कौशल सीखने का नहीं था, बल्कि खुद को समझने, आत्मविश्वास बढ़ाने और खुद पर विश्वास करने का था। उसने अपने साथियों के साथ खुशियां और परेशानियां साझा कीं, त्योहार मनाए और हर छोटी सफलता का साथ में जश्न मनाया। एनवाईसीएस के कार्यक्रमों में शिवानी को डांस और रैंप वॉक में भाग लेने के भी अवसर मिले। यह ऐसे अनुभव थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था।

**एनवाईसीएस की टीम द्वारा समझाने पर आखिरकार शिवानी का परिवार मान गया। शिवानी ने न केवल खुद की स्किल बढ़ाने वाला कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि प्रशिक्षण के बाद काम भी शुरू किया। शिवानी के लिए यह सफर सिर्फ रोजगार योग्य कौशल सीखने का नहीं था, बल्कि खुद को समझने, आत्मविश्वास बढ़ाने और खुद पर विश्वास करने का था।**

आज शिवानी पीएसी कॉस्मेटिक्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है और लगभग 60,000-70,000 रुपये प्रति माह कमा रही है। वह अब अपने परिवार का महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन गई है। उसके पिता जो कभी उसे ब्यूटी कोर्स में एडमिशन करवाने में संकोच कर रहे थे, अब गर्व से शिवानी की सफलता की कहानी सबको बताते हैं। शिवानी ने युवा सहकार को बताया, 'आज मैं जो कुछ भी हूं वह माता-पिता की और एनवाईसीएस के समर्थन से हूं। एनवाईसीएस ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं जीवन भर एनवाईसीएस की आभारी रहूंगी।'

NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
Chlorophyll Charger
Yield Booster
Climate Smart Farming
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Seed Primer | Growth Enhancer | Yield Booster
Less Cost, More Profits
Suitable for all Crops

NYCS

# National Yuva Co-operative Society Limited

## Empowering Financial Independence

## Our Services

**Loans:** Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.
**Deposits:** Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.
**Simplified Process:** Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

## Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

## Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

## Contact Us

209, 2nd Floor, A2B,
Vardhman Janak Market,
Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, let's build a brighter financial future!